प्रो॰ राम देव भंडारी: सेंट्रल स्कूल में पढ़कर भी वे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप सवाल पूछ लें।

प्रो॰ राम देव भंडारी: सरकार यह बताए कि राज्य सरकारों से वार्ता करके, विचार करके इस संबंध में क्या कोई समाधान निकालने जा रही है?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, दिल्ली के संदर्भ में अभी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसके हिसाब से जो 15 फीसदी economically weaker sections के लोग हैं, उनके लिए सीट्स उन्होंने रिजर्व की हैं। इसी तरह के जो कानून हैं, जो स्टेट्स के अन्दर भी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती हैं और बना करके, स्कूल वालों से बात करके, उनको इंप्लिमेंट कर सकती हैं। जहां तक सवाल पैदा होता है और मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरे मुल्क में तकरीबन डेढ़ लाख स्कूल हैं और तकरीबन ग्यारह लाख middle schools या जिसको ...(**व्यवधान**)...

श्री उदय प्रताप सिंह: सर, समवर्ती सूची का मतलब यह नहीं कि...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: उदय प्रताप जी, आप बैठ जाएं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: तो इसके लिए स्टेट को ही करना पड़ेगा।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: उदय जी, आप जवाब सुन लें।...(**व्यवधान**)...आप जवाब सुन लें।...(**व्यवधान**)...

श्री उदय प्रताप सिंह: समवर्ती सूची का मतलब यह होता है कि आपको यह जानने का अधिकार है कि ठीक हो रहा है या नहीं।

श्री सभापति: उदय प्रताप जी, आप जवाब सुन लें।...(**व्यवधान**)...प्लीज...प्लीज...(**व्यवधान**)...

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, यह state subject है और स्टेट इस पर फैसला कर सकती है। हम लोगों से जो मदद होगी, वह हम लोग कर सकते है और उसके लिए हम तैयार हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री उदय प्रताप सिंह: सर, ये बार-बार कह रहे हैं कि state subject हैं, लेकिन आपको जानने का अधिकार है कि स्टेट में क्या हो रहा है? आप कैसी बातें कर रहें है।...(**व्यवधान**)...

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: यह राज्य ही तो फैसला करेगा।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: देखिए...(**व्यवधान**)...डा॰ कपिला वात्स्यायन, पूछिए।

डा॰ कपिला वात्स्यायन: सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि यह जो neighbourhood school की योजना थी, कोठारी कमीशन ने 1964 में इसकी बात की थी और क्या अभी हाल में सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड ऑफ ऐजुकेशन में यह मुद्दा फिर से उठाया गया है या नहीं? अगर नहीं उठाया है, तो क्यों नहीं उठाया गया है?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, neighbourhood school का concept जो भी हो, अभी यह कंसिडरेशन में नहीं है। यह एक सोच है, यह डिसकशन में जरूर आया है, लेकिन हिंदुस्तान में neighbourhood school के concept पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है।

सीपत ताप विद्युत संयंत्र से विद्युत

†*146. **श्री श्रीगोपाल व्यास:**
श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ के सीपत एनटीपीसी संयंत्र से राज्य को प्रथम चरण में 300 मेगावाट और दूसरे चरण में 200 मेगावाट विद्युत आपूर्ति किए जाने का आश्वासन दिया गया था;

†Original notice of the question was received in Hindi.

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी आपूर्ति की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) दिनांक 20.1.2007 को एनटीपीसी सीपत की 765 केवी पारेषण प्रणाली के उद्घाटन के दौरान सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (एसटीपीपी) से छत्तीसगढ़ राज्य को पहली यूनिट के चालू होने से एक वर्ष के लिए 300 मेगावॉट विद्युत आबंटन के लिए छत्तीसगढ़ के अनुरोध पर अनुकूलत: विचार किया गया। आबंटन के लिए प्रचलित केंद्रीय पूल के आधार पर सीपत एनटीपीसी के चरण-II (2x500 मेगावाट) से छत्तीसगढ़ के लिए 158 मेगावाट के संपूर्ण हकदार आबंटन की व्यवस्था कर दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के साथ क्षेत्र के अन्य राज्यों/संघ शासित राज्यों में विद्युत की कमी का ध्यान रखते हुए, सीपत एनटीपीसी के चरण-II की पहली यूनिट के व्यावसायिक परिचालन की तिथि से पश्चिमी क्षेत्र में केंद्रीय उत्पादक केंद्रों के अनाबंटित विद्युत पूल में से छत्तीसगढ़ के लिए लगभग 75 मेगावाट अनाबंटित विद्युत की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

उपरोक्त के अलावा, छत्तीसगढ़ को सीपत एसटीपीपी चरण-I (3x60 मेगावाट) से 313 मेगावाट विद्युत आबंटित कि गई हैं। छत्तीसगढ़ को सीपत एसटीपीपी चरण-I के अनाबंटित कोटे में सी भी आबंटन किया जाएगा।

(ख) और (ग) सीपत एनटीपीसी चरण-II की पहली यूनिट के मई, 2007 में समकालिक (सिंक्रोनाइज्ड) किया गया। नवंबर, 2007 में इसका कोयले से परिचालन शुरू हुआ। तथापि, छत्तीसगढ़ सरकार के दिनांक 28.9.2007 के पत्र द्वारा जल आबंटन निरस्त कर दिए जाने के कारण लगातार उत्पादन नहीं किया जा सका। इस कारण यह राज्य और पश्चिमी क्षेत्र उत्पादन योग्य विद्युत का उपयोग उस समय नहीं कर सके जबकि क्षेत्र विद्युत की भारी कमी का सामना कर रहा था।

Power from Sipat Thermal Power Project

†*146. SHRI SHREEGOPAL VYAS:
SHRI BALVANT *ALIAS* BALAPTE:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether an assurance of supplying 300 Megawatt in the first phase and 200 Megawatt in the second phase from NTPC's sipat thermal Power Project in the State had been given to Chhattisgarh:

(b) if so, whether it was supplied; and

(c) if not, the reasons therefore?

THE MINISTER OF POWER (SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) During the inauguration of the 765kV transmission system at NTPC Sipat on 2.01.2007, the request of Chhattisgarh to allocate 300 MW of pwer from Sipat Super Thermal Power Project (STPP) to Chhattisgarh State for a period of one year since the commissioning of the first unit was taken for favourable consideration. Chhattisgarh has been allocated its

†Original notice of the question was received in Hindi.

entire entitled allocation of 158 MW from State II (2x500 MW) of Sipat STPP based on the prevailing Central formula for allocation. Chhattisgarh has also been allocated additional unallocated power of about 75 MW from the pool of unallocated power of Central Generating Stations in the Western Region with effect from the date of commercial operation of the first unit of Stage II of Sipat STPP, keeping in view the shortage of power in Chhattisgarh as well as that of other States/UTs in the Region.

Besides the above, Chhattisgarh has been allocated 313 MW of power from Stage-I (3x660 MW) of Sipat STPP. Chattisgarh will also get allcoation from the unallocated quota of Sipat STPP Stage-I.

(b) and (c) The first unit (500 MW) of Sipat STPP Stage-II was synchronized in May, 2007. The operation on coal commenced in November, 2007. However, continuous generation could not be done due to cancellation of water allocation by the Government, of Chhattisgarh *vide* letter dated 28.9.2007. This has deprived the State and the Western Region from the utilization of generateable power at a time when the region is facing severe power shortage.

श्री श्रीगोपाल व्यास: मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने यह तो मान लिया कि 300 की घोषणा की गई थी, पर अभी केवल 158 मेगावॉट दिया जा रहा है और 150 की घोषणा के बजाय 75 दिया जा रहा है। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जो आपने कहा है कि पानी बंद कर दिया गया है, हमारी जानकारी यह है कि चूंकि परिवारों को काम नहीं दिया गया और मुआवजा नहीं दिया गया, इसलिए पानी बंद हो गया है। तो क्या मंत्री जी कृपा करके बताएंगे कि उन सारे परिवारों को काम कब दे दिया जाएगा, यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न भी पूछ लेता हूं क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, क्या राज्य सरकार ने महानदी से पानी लेने के लिए आपसे कहा है?

श्री सुशील कुमार शिन्दे: सभापति महोदय, जिस प्रश्न का उत्तर माननीय सदस्य पूछ रहे है।, अभी कुछ घंटे पहले मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री जी से बात की थी और 500 लोगों को नौकरी देने की बात वे कर रहे थे, तो 500 मेगावॉट का यूनिट है, जहां पच्चीस-पचास लोग काम पर लग सकते है करीब सौ लोग immediately लेंगे, इस तरह की बात हम लोगों ने की है। पांच सौ (500) तो नहीं ले सकते और खाली बैठकर वहां तनख्वाह नहीं दे सकते हैं। मैंने मुख्य मंत्री जी से बात की है और पानी बंद करना ठीक नहीं है, यह भी मैंने कहा है। आज देश में बिजली बहुत कम है। यदि पानी बंद करेगे, तो जो पूरा पश्चिमी क्षेत्र है, उसमें बिजली ही नहीं मिलेगी। यह concurrent subject है, इसलिए मैं विनती करूंगा कि आप ज़रा उस राज्य को बोल दीजिए कि पानी जल्दी दीजिए, हम दूसरा यूनिट भी जल्द ही चालू करेंगे। फेज-I के लिए भी हम तैयारी कर रहें हैं। तीन सौ मेगावाट बिजली देना कोई बड़ी बात नहीं है। हम उस पर भी विचार कर रहें है। कि किस तरह से देनी है क्योंकि जब मध्य प्रदेश में से bifurcation हो गया था तब इधर बिजली थोड़ी ज्यादा आ गयी थी इसलिए कट करके थोड़ी दे दी है। ये सब बातें चर्चा की हैं। मैं इस सबंध में मुख्य मंत्री जी से बात करूंगा। मैंने यह भी कहा है कि इन सब प्रश्नों पर बात करने के लिए मैं खुद छत्तीसगढ़ आऊंगा और तब इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Establishment of new IIT in Gujarat

*147. SHRI VIJAYKUMAR RUPANI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Prime Minister has announced the establishment of a